

प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
28.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

“ मुख्य समाचार ”

- प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित— 73 घंटे चली सदन की कार्यवाही— कई महत्वपूर्ण बिल पारित।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बजट सत्र को बताया ऐतिहासिक— कहा— समाज के हर वर्ग का रखा ख्याल।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा— विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में उठाया।
- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता व पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भत्ता देने की घोषणा की।

समाचार विस्तार से.....

सत्र खत्म

प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। शिमला में 10 मार्च से शुरू हुए इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुईं और सदन की कार्यवाही 73 घंटे चली। सत्र के दौरान 8 बिल भी पास किए गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

डिस्पैच— शिमला में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही 73 घंटे चली और इसकी उत्पादकता एक सौ 10 फीसदी रही। सत्र समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र में 5 सौ 72 तारांकित और एक सौ 96 अतारांकित सवालों के जवाब दिए गए। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं जिसका लोगों को लाभ होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया गया। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया गया। सरकार ने विधायकों के टैलीफोन भत्ते के 15 हजार रुपए के अलावा बिजली व पानी बिल भत्ता खत्म कर दिया है।

रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला।

प्रश्नकाल

प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राजधानी शिमला में 66 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है, जिनमें आवासीय भवनों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। शिमला में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यह जानकारी दी। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल कर्मचारियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए आवास की अलॉटमेंट करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग जी.ए.डी. को जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिमला में स्थित विधायक सदन मेट्रोपोल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन के मरम्मत कार्य के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि असुरक्षित भवनों में रह रहे सभी कर्मचारियों को अगले दो महीनों के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार का धर्मशाला में प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में कुल 8 हजार एक सौ 55 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने

बताया कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023–24 में 3 हजार 7 सौ 30 और 2024–25 में 4 हजार 4 सौ 25 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मटौर–शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग फोरलेन बनेगा और आठ पैकेज में इसका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन बनाने संबंधी डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन एन.एच.ए.आई. ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है और इस बारे में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे।

महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि इस साल की पहली जनवरी से लागू होगी और इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों व 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

युवा संसद

नेहरू युवा केंद्र संगठन शिमला द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 'विकसित भारत युवा संसद-2025' का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और उनकी ऊर्जा, विचार व नवाचार समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस यात्रा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को राष्ट्र के सक्रिय और सतर्क युवा के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। इस राज्यस्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में पहले दिन विभिन्न जिलों के 32 प्रतिभागियों ने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

इंदु गोस्वामी

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2016–17 में हिमाचल प्रदेश में हिमालय सर्किट के तहत 68 करोड़ 34 लाख रूपए की 7 विकास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि हिमालय सर्किट योजना के तहत इन क्यारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर और चम्बा शामिल हैं। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सैंट्रल सैक्टर में लॉन्च की गई स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत देश में पर्यटन ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आर.एस.एस.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 2 अक्टूबर 2025 को सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। संगठन विस्तार सदभाव और एकता के संबंध में आज शिमला में संघ के हिमाचल प्रांत के संघचालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा ने एक पत्रकार वार्ता में संघ के सौ वर्ष में हुए सुदृढ़ीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठकें बैंगलुरु में आयोजित की गईं और इस दौरान संगठन के विस्तार, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय

एकता व हिन्दू समाज की सुरक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया। रांगड़ा ने बताया कि संघ की शाखाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं व संन्यासियों के साथ हो रही लूटपाट पर चिंता जताते हुए केन्द्र सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने आज लोकसभा में भारत दूर संचार निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को तीसरे वेतन आयोग के लाभ देने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस उपक्रम में 30 हजार ग्रुप-सी व डी के कर्मचारी हैं और 5 हजार पेंशनर हैं जिन्हें अभी तक तीसरे वेतन संशोधन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

“मुख्य समाचार एक बार फिर”

- प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित— 73 घंटे चली सदन की कार्यवाही— कई महत्वपूर्ण बिल पारित।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बजट सत्र को बताया ऐतिहासिक— कहा— समाज के हर वर्ग का रखा ख्याल।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा— विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में उठाया।
- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता व पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भत्ता देने की घोषणा की।
